दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

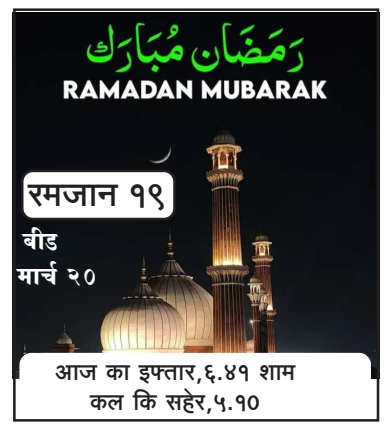

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-२२६ वा | गुरूवार २० मार्च २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए 'सुरक्षित और समृद्ध महाराष्ट्र' का निर्माण करेंगे-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जमीर काज़ी, मुंबई

महाराष्ट्र एक स्थिर और प्रगतिशील राज्य है, जो शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता है। राज्य की कानून-व्यवस्था को कोई भी प्रभावित करने की कोशिश करेगा, तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष २०२५-२६ के गृह विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान यह आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि महाराष्ट्र की शांति को भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर की घटना में पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

३६,६१४.६८ करोड़ रुपये के बजट को मिली मंजूरी.

गृह विभाग के लिए ३६,६१४ करोड़ ६८ लाख ९ हजार रुपये की मांगों को विधानसभा में मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अपराधियों को सजा मिलना जरूरी है। राज्य सरकार अपराधियों पर कार्रवाई कर अपराध सिद्ध करने की दर बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

उन्होंने बताया कि देशभर में अपराध दर के मामले में महाराष्ट्र आठवें स्थान पर है और राज्य का कोई भी शहर शीर्ष पांच अपराधग्रस्त शहरों में नहीं है। शहरी क्षेत्रों में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम है। २०२३ की तुलना में २०२४ में अपराधों में २,५८६ मामलों की कमी आई है।

महिलाओं पर अपराध और सरकार के प्रयास

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि २०१३ के बाद से महिलाओं पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा बदली गई है। अब छेड़छाड़ को भी बलात्कार के समान अपराध माना जाता है।

महिलाओं की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

पहले महिलाएं अत्याचार की शिकायत करने से हिचकिचाती थीं, लेकिन अब वे खुद आगे आकर शिकायत दर्ज करवा रही हैं।

२०२४ में दर्ज बलात्कार मामलों में ९९.८% घटनाएं परिचित व्यक्ति द्वारा की गई थीं, जबकि अनजान लोगों द्वारा अपराध की दर ९९.४८% रही।

९०% मामलों में ६० दिनों के भीतर आरोपपत्र दायर किया गया है।

इस दर को १००% तक ले जाने के लिए प्रयास जारी हैं।

महिला सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं

हर पुलिस थाने में महिला सहायता कक्ष स्थापित किया गया है, जहां महिला अधिकारियों के माध्यम से ही शिकायत दर्ज की जाती है।

महिला सुरक्षा के लिए 'दामिनी पथक', 'निर्भया कक्ष' और 'भरोसा सेल' स्थापित किए गए हैं। स्कूल-कॉलेजों में पुलिस अधिकारी जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। निर्भया फंड के २५० करोड़ रुपये में से २३६ करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। डायल ११२ - देश में दूसरी सबसे तेज सेवा डायल ११२ पर कॉल करने पर त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस सेवा की प्रतिक्रिया समय देश में दूसरे स्थान पर है, और इसे पहले स्थान पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह सेवा केंद्र सरकार की सीसीटीएनएस प्रणाली से जुड़ी हुई है। ऑपरेशन मुस्कान' से बच्चों की सुरक्षा लापता बच्चों की खोज के लिए ऑपरेशन मुस्कान' चलाया जा रहा है। अब तक १२ चरण पूरे किए गए हैं, और ३८,९१० बच्चों को उनके परिवार से मिलाया गया है। अपराधियों की दोषसिद्धि दर बढ़ाने का लक्ष्य २०१५ में महाराष्ट्र की दोषसिद्धि दर ३३% थी, जो २०२४ में ५०% तक पहुंच गई है। अगले वर्षों में इसे ७५% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। न्याय-वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को किया जाएगा सशक्त नए कानूनों के तहत

▶▶पान ४ पे

१८५७ के संग्राम में बहादुर शाह जफर की भूमिका और उनकी हिंदू-मुस्लिम एकता की पहल

(मौके पर, बहादुर शाह जफर की तस्वीर को औरंगजेब की तस्वीर समझकर जलाने की खबर आई)

बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम सम्राट थे। १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में बहादुर शाह और नाना साहब पेशवा ने भाग लिया था और सैनिकों ने उन्हें नेतृत्व स्वीकार किया था, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं।

उस समय हिंदू-मुस्लिम राजा और संस्थान, सभी का एक ही दुश्मन था - अंग्रेज। अंग्रेजों ने इन राजाओं और संस्थानों का सम्मान खत्म कर दिया और उनकी तनख्वाहें भी बंद कर दी थीं। इन लोगों ने अपनी पूर्व निर्धारित मांगों को लेकर अपने राजदूतों या वकीलों को इंग्लैंड भेजा था। बहादुर शाह के पूर्वज अकबर शाह ने राजा राममोहन राय को अपना वकील बनाकर इंग्लैंड भेजा था, जबकि नाना साहब पेशवा के वकील अज़ीमुल्लाह थे।

राजा राममोहन राय ने अरबी और फ़ारसी भाषाओं के साथ इस्लाम और सूफ़ी मत का अध्ययन किया था। उन्हें हाफिज और सादी की कविताएं प्रिय थीं। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी और वे इंग्लैंड जाने वाले पहले भारतीय थे। दूसरी ओर, नाना साहब पेशवा के वकील अज़ीमुल्लाह का इतिहास काफी अलग है। वे फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा के अच्छे जानकार थे।

अज़ीमुल्लाह ने नाना साहब पेशवा की ओर से लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के समक्ष अपना पक्ष रखा, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि, उन्होंने इंग्लैंड के उच्च परिवार की महिलाओं को प्रभावित किया था। इस पर विस्तृत विवरण 'इंडियन प्रिंस एंड द इंग्लिश उमराव' नामक पुस्तक में दिया गया है, जिसमें लंदन की महिलाओं द्वारा भेजे गए पत्र भी प्रकाशित किए गए हैं।

१८५७ में सैनिकों के नेतृत्व को स्वीकार करना

हालांकि बहादुर शाह जफर ने सैनिकों के नेतृत्व को मजबूरी में स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया था। १२ मई १८५७ को बहादुर शाह ने एक सरकारी संस्था' की स्थापना की और मान्यवर सरदारों से दरबार को भर दिया। मिर्ज़ा मुगल को सेनापतियों का प्रधान और अन्य राजकुमारों को सेना के प्रमुख पद दिए गए।

दिल्ली के भयभीत वातावरण के कारण बहादुर शाह ने व्यापारियों से हाथी पर बैठकर लेन-देन शुरू करने का आग्रह किया था। इस संस्था में सैन्य और राष्ट्रीय व्यवस्था संभालने वाले प्रतिनिधि शामिल थे।

▶▶पान ४ पे

मौलाना आज़ाद की सौगात, १५० व्यापारियों को ४ करोड़ ८० लाख और २२ छात्रों को १ करोड़ १८ लाख का कर्ज वितरित

संचालक शेख तैय्यब की सक्रियता से बीड़ जिले के व्यापारी और छात्र हुए लाभान्वित

बीड़। संवादाता

जब कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, तो आम जनता को उसका लाभ जरूर मिलता है। मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के निदेशक पद पर नियुक्ति के बाद, केवल चार महीनों में १५० व्यापारियों और २२ छात्रों को कुल ५ करोड़ ९२ लाख रुपये का कर्ज वितरित किया गया। इससे न केवल व्यापारियों के व्यवसाय में वृद्धि होगी बल्कि छात्रों की शैक्षणिक बाधाएं भी दूर होंगी। इन लाभार्थियों में चार छात्र विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने वाले भी शामिल हैं।

चार महीने पहले सायं. दैनिक बीड़ रिपोर्टर के संपादक शेख तैय्यब को मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल का निदेशक नियुक्त किया गया। पहले दो महीनों में ही उन्होंने

मराठवाड़ा सहित पूरे राज्य का दौरा कर महामंडल के उद्देश्य और योजनाओं को सभी के समक्ष रखा। शैक्षणिक कर्ज की आवश्यकता को लेकर समय-समय पर बैठकों में चर्चा की गई।

कर्ज योजना से सैकड़ों लोगों को मिला लाभ

बीड़ जिले में महामंडल की मुदत कर्ज योजना के तहत १५० लाभार्थियों को ४ करोड़ ८० लाख रुपये का व्यवसायिक कर्ज स्वीकृत कर उन्हें मंजूरी पत्र वितरित किए गए। वहीं शैक्षणिक कर्ज योजना के तहत २२ छात्रों को १ करोड़ १० लाख २०० रुपये का कर्ज स्वीकृत किया गया।

इसके अलावा, विदेश में पढ़ाई करने वाले ४ छात्रों को ८२ लाख ५० हजार रुपये का कर्ज मंजूर कर उनकी शिक्षा को समर्थन दिया गया।

संचालक शेख तैय्यब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यवसायियों और छात्रों को बड़ी राहत प्रदान की है। महामंडल द्वारा तय समयसीमा में लगभग २०० फाइलें अभी भी मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं, जिन्हें जल्द से जल्द स्वीकृति देने का प्रयास किया जा रहा है।

इस अवसर पर जिला प्रबंधक इमरान कादरी, शाहेद पटेल, सय्यद नदीम, सोहेल पटेल, फैय्याज कुरैशी, समीर पटेल आदि मौजूद थे।

कर्ज मंजूरी के लिए पैसे न दें, दलालों से बचें

मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से कर्ज मंजूरी में किसी भी दलाल को पैसे देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति फाइल स्वीकृत करवाने के नाम पर कमीशन या पैसे मांगता है, तो उससे सावधान रहें। किसी

▶▶पान ४ पे

अमेरिका में भारतीय शोधकर्ता बदर खान को किया गया गिरफ्तार

नवी दिल्ली: संवादाता

अमेरिका के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में पढ़ रहे एक भारतीय छात्र बदर खान सूरी को गिरफ्तार कर लिया गया है. वो वहां पोस्ट डॉक्टरेट फेलो थे और अब उन्हें अमेरिका से निर्वासित किया जाएगा.

खान के वकील के अनुसार, उन्हें सोमवार रात वर्जिनिया स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया. पोलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ नकाबपोश एजेंट उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचे. गिरफ्तारी के कागजात के अनुसार, इन एजेंटों ने खुद को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का अधिकारी बताया

▶▶पान ४ पे

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

आत्महत्या ग्रस्त किसानों की विधवा महिलाओं का अंबाजोगाई में मौन मार्च

अंबाजोगाई, १९ मार्च (प्रतिनिधि) – आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवा महिलाओं और उनके परिवारों को न्याय दिलाने तथा उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए बुधवार को अंबाजोगाई में एक विशाल मौन मार्च निकाला गया। यह मार्च राजीव गांधी चौक से शुरू हुआ और उपजिल्हाधिकारी कार्यालय तक पहुंचा, जहां महिलाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपजिल्हाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा।

मूक मोर्चे का नेतृत्व अड. संतोष पवार ने कियाइस मूक मोर्चे का नेतृत्व 'आधार माणूसकी' संस्था के अध्यक्ष अड. संतोष पवार ने किया। इस दौरान शेतकरी संघटना के विभागीय अध्यक्ष कालिदास आपेट, किसानपुत्र आंदोलन के सुदर्शन रापतवार, अच्युत गंगणे समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

मुख्य मांगें – हर विधवा परिवार को २५ लाख रुपये की सहायता मिले

यह मौन मार्च दोपहर १२ बजे राजीव गांधी चौक से शुरू होकर मोढा, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक होते हुए उपजिल्हाधिकारी कार्यालय पहुंचा। यहां महिलाओं ने अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा।

महिलाओं ने अपनी मांगों में कहा कि – प्रत्येक आत्महत्या ग्रस्त किसान परिवार को २५ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। परिवार के बच्चों को स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जाए। उच्च शिक्षा के लिए इन परिवारों को बिना गारंटी के कर्ज दिया जाए। हर महीने १०,००० रुपये गुजारा भत्ता दिया जाए। प्रत्येक परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय योजना का लाभ दिया जाए। सरकार की बालसंगोपन योजना का लाभ इन परिवारों को प्राथमिकता से दिया जाए। बच्चों को सरकारी छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाए। कृषि और गृह उद्योग के लिए तत्काल कर्ज उपलब्ध कराया जाए। संजय गांधी निराधार योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि बढ़ाई जाए। सरकारी योजनाओं का लाभ आत्महत्या ग्रस्त किसानों के परिवारों को तुरंत दिया जाए। उपवास रखकर महिलाओं ने जताया विरोध शेतकरी सहवेदना दिन के अवसर पर महिलाओं ने कड़ी धूप में उपवास रखते हुए यह मौन मोर्चा निकाला। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और किसान शामिल हुए।

श्रीराम देवस्थान की जमीन सुरक्षित नहीं-आ.विजयसिंह पंडित

मुंबई, १९ मार्च (प्रतिनिधि) – ग्राम पंचायत का कार्य अतिक्रमण हटाना होता है, लेकिन चकलांबा ग्राम पंचायत ने खुद ही श्रीराम देवस्थान की जमीन पर अतिक्रमण कर कचरा डंपिंग यार्ड का निर्माण शुरू कर दिया है। लोग कहते हैं कि महायुती के शासन में 'रामराज्य' चल रहा है, लेकिन इस रामराज्य में श्रीराम देवस्थान की जमीन भी सुरक्षित नहीं है। यह चिंता विधायक विजय सिंह पंडित ने आज विधानसभा में व्यक्त की।

उन्होंने गेवराई तालुका में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन जल आपूर्ति योजनाओं में अनियमितताओं की जांच के लिए डखढ गठित करने की मांग की।

जल जीवन मिशन की धांधली और श्रीराम देवस्थान पर अतिक्रमण का मुद्दा उठा

विधानसभा में पानी आपूर्ति और स्वच्छता विभाग की मांगों पर चर्चा के दौरान, आ. विजय सिंह पंडित ने दो प्रमुख मुद्दे उठाए:

जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजनाओं में भ्रष्टाचार। चकलांबा ग्राम पंचायत द्वारा श्रीराम देवस्थान की भूमि पर किए गए अतिक्रमण का मुद्दा। उन्होंने कहा कि गेवराई तालुका के १९२ गांवों के लिए १७२ करोड़ रुपये की लागत से १७७ जल आपूर्ति योजनाएं स्वीकृत हुई थीं। लेकिन तय समय में एक भी योजना पूरी नहीं हुई।

गर्मी के मौसम में भी १९२ गांवों में से १०% गांवों में भी सुचारू जल आपूर्ति नहीं हो रही है। थ-झउजड प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी कोष के करोड़ों रुपये बर्बाद हो गए हैं।

'प्रगति कंस्ट्रक्शन' जैसे ठेकेदार करोड़ों रुपये लेकर फरार हो चुके हैं।

इस घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल (डखढ) गठित करने की जरूरत है। चकलांबा ग्राम पंचायत पर अतिक्रमण का आरोप

चकलांबा ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती खेडकर के कार्यकाल में श्रीराम देवस्थान की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत पवन लाहोटी ने की थी। लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पानी आपूर्ति और स्वच्छता विभाग के परियोजना निदेशक राजेंद्र मोराले ने इस निर्माण को रोकने के बजाय गट विकास अधिकारी को यह जांचने के लिए पत्र लिखा कि जमीन पर वास्तव में अतिक्रमण हुआ है या नहीं।

क्या राजेंद्र मोराले केवल कागजी कार्रवाई कर चकलांबा ग्राम पंचायत की सरपंच खेडकर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? यह सवाल चकलांबा के नागरिकों के बीच उठ रहा है।

ठेवीदारों के दबाव में ज्ञानराधा पर एमपीआयडी प्रस्ताव मंजूर-प्रो.उबाळे

दो साल से जारी आंदोलन को मिली सफलता

बीड (प्रतिनिधि) – दिवालिया हो चुकी मल्टीस्टेट सहकारी संस्थाओं में सबसे अधिक जमाकर्ताओं वाली ज्ञानराधा मल्टीस्टेट पर आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने चझखऊ (महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट) प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र में की।

ठेवीदार कृती समिति के राज्य समन्वयक एवं स्वाभिमानी संघटना के जिला अध्यक्ष प्रो. सचिन उबाळे ने कहा कि सरकार ने यह फैसला जमाकर्ताओं के निरंतर दबाव के कारण लिया है। पिछले दो वर्षो से जमाकर्ताओं की मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन को इस निर्णय के रूप में सफलता मिली है।

मराठवाड़ा की कई मल्टीस्टेट संस्थाएं दिवालिया

बीड जिले में ज्ञानराधा मल्टीस्टेट, साईराम मल्टीस्टेट, राजस्थानी मल्टीस्टेट (पतसंस्था), जिजाऊ मल्टीस्टेट, शुभ कल्याण मल्टीस्टेट, मातोश्री अर्बन, लक्ष्मीमाता अर्बन और मराठवाड़ा अर्बन (माजलगांव) जैसी कई वित्तीय संस्थाएं दिवालिया हो चुकी हैं। इनमें मराठवाड़ा के लाखों जमाकर्ताओं के करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं।

लगातार आंदोलन और धरनों से मिली सफलता

ज्ञानराधा मल्टीस्टेट में राज्यभर के सबसे अधिक जमाकर्ताओं के पैसे अटके हैं। इन जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाने के लिए प्रो. सचिन उबाळे के नेतृत्व में बार-बार धरने और आंदोलन किए गए।

बीड पुलिस ने आंदोलन के दबाव में सुरेश कुटे सहित सभी मल्टीस्टेट संस्थाओं के प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया।

चझखऊकानून के तहत कार्रवाई और अर्चना कुटे की गिरफ्तारी की मांग पहले से की जा रही थी। पहले सरकार ने चझखऊप्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसमें कुछ खामियां पाई गईं, जिससे इसे वापस कर दिया गया।

प्रो. उबाळे ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर खामियां दूर करने की मांग की, जिससे आठ दिन के भीतर इसे फिर से भेजा गया।

मुख्यमंत्री की घोषणा से जमाकर्ताओं को राहत

अंततः, बीड पुलिस द्वारा भेजे गए ज्ञानराधा मल्टीस्टेट के खिलाफ चझखऊ प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने विधानसभा में की। प्रो. उबाळे ने इसे जमाकर्ताओं के आंदोलन की दूसरी बड़ी जीत बताया।

इन नेताओं का जताया आभार

ज्ञानराधा और अन्य मल्टीस्टेट संस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए विधायक नितेश राणे, सुरेश अण्णा धस, प्रकाश दादा सोळंके, नारायण कुचे, बबनराव लोणीकर और मेघना बोर्डीकर का प्रो. सचिन उबाळे ने आभार व्यक्त किया।

अवादा कंपनी के गोदाम से केबल चोरी, ११ लाख की तांबे की केबल ले उड़े चोर

केज, १९ मार्च (प्रतिनिधि) – अवादा कंपनी के गोदाम से ११ लाख २६ हजार रुपये की तांबे की केबल चोरी होने की घटना सामने आई है। यह चोरी १० मार्च की रात को हुई थी, जिसके बाद १८ मार्च को सहायक स्टोर मैनेजर आशुतोष जयराम सिंह की शिकायत पर केज पुलिस स्टेशन में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

मध्यरात्रि में अज्ञात चोरों ने दी वारदात को अंजाम

केज तालुका के मस्साजोग शिवार में पवनचक्की निर्माण का काम कर रही अवादा कंपनी के गोदाम से यह चोरी १० मार्च की रात करीब ६:३० बजे से १२ बजे के बीच हुई। अज्ञात चोर ११ लाख २६ हजार रुपये मूल्य की तांबे की केबल चोरी कर ले गए।

१८ मार्च की रात ११ बजे इस मामले में सहायक स्टोर मैनेजर आशुतोष जयराम सिंह की शिकायत पर केज पुलिस में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

सीसीटीवी फुटेज नहीं होने से पुलिस जांच में अड़चन

मामले की जांच कर रहे पुलिस उपनिरीक्षक राकेश बनसोडे ने कंपनी के अधिकारियों से सीसीटीवी फुटेज की मांग की, लेकिन फुटेज उपलब्ध नहीं था। आगे की जांच पुलिस निरीक्षक वैभव पाटील के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक राकेश बनसोडे कर रहे हैं।

२५० की आबादी वाले क्षेत्रों में 'पीएमजीएसवाई' लागू करने के लिए केंद्र से अनुरोध-मंत्री जयकुमार गोरे

विशेष प्रतिनिधि, मुंबई, १९ मार्च

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (झचत्रख्ध) फिलहाल कम से कम ५०० की आबादी वाले क्षेत्रों में लागू की जाती है, लेकिन इसे २५० की आबादी वाले गांवों में भी लागू करना जरूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार से लगातार अनुरोध किया जा रहा है। यह जानकारी राज्य के ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे ने आज विधानसभा में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान दी।

इस मुद्दे को विधानसभा सदस्य समीर कुणावार ने उठाया था, जिसमें प्रकाश सोळंके, प्रशांत बंब, कैलास पाटील और किरण लहामटे ने भी चर्चा में भाग लिया।

गुणवत्तापूर्ण सड़कों पर जोर

मंत्री जयकुमार गोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाए जाने वाले सभी सड़कें दर्जेदार, मजबूत और गुणवत्ता मानकों के अनुसार बनाई जा रही हैं।

सड़क निर्माण की गुणवत्ता की सख्त जांच की जाती है।

इन सड़कों की जांच कार्यकारी अभियंता, राज्य गुणवत्ता निरीक्षक और राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षक द्वारा की जाती है।

बिना जांच के किसी भी बिल का भुगतान नहीं किया जाता।

निकृष्ट सड़क निर्माण पर होगी सख्त कार्रवाई

यदि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों की गुणवत्ता खराब पाई जाती है, तो इसकी जांच होगी।

यदि किसी ठेकेदार को काम शुरू करने का आदेश मिलने के बावजूद निर्माण कार्य में देरी होती है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

नंदुरबार जिले में ७७ में से ६८ सड़कें पूरी, ९ पर काम जारी

ग्राम विकास मंत्री गोरे ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण में नंदुरबार जिले के धडगांव और अक्कलकुवा तालुकों में ७७ सड़क निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई थी। इनमें से ६८ काम पूरे हो चुके हैं, जबकि ९ कार्य प्रगति पर हैं। ये सभी सड़कें मई २०२५ तक पूरी कर ली जाएंगी।

पान १ से

कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए 'सुरक्षित...

फॉरेंसिक तकनीक को मजबूत किया जा रहा है। मोबाइल फॉरेंसिक वैन शुरू की गई हैं, जो अपराध स्थलों से ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए साक्ष्य सुरक्षित रखेंगी। अपराध स्थलों का वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य किया जा रहा है। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए कड़े कदम राज्य में साइबर अपराध रोकने के लिए ५१ प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। नवी मुंबई में महासाइबर' मुख्यालय स्थापित किया गया है। देशभर में यह सबसे आधुनिक साइबर सुरक्षा प्रणाली बनने की ओर अग्रसर है। साइबर धोखाधड़ी की गई रकम को गोल्डन आवर' में वापस लाने की योजना बनाई गई है। २०२४ में ४४० करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी को रोका गया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराध शिकायतों के लिए १०४५ टोल फ्री नंबर शुरू किया है।

ऑपरेशन ब्लैक फेस' – बच्चों से जुड़ी ऑनलाइन अश्लीलता पर शिकंजा

ऑनलाइन बाल यौन शोषण के मामलों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए 'ऑपरेशन ब्लैक फेस' शुरू किया गया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस तरह की सामग्री हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

नशा विरोधी अभियान को मिलेगा बल हर पुलिस थाने में नशा विरोधी सेल' शुरू किया गया है। पुलिस विभाग में ड्रग्स के मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों को बर्खास्त करने का प्रावधान किया गया है। मेडिकल दुकानों को नशीली दवाओं की बिक्री पर सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। नागपुर में न्याय-वैज्ञानिक विज्ञान विश्वविद्यालय केंद्र सरकार ने देश में तीन न्याय-वैज्ञानिक विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इनमें से एक विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में खोला जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपराध नियंत्रण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (-ख) आधारित मार्वल' प्रणाली विकसित की जा रही है। डेटा माइनिंग के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सीसीटीवी निगरानी को मजबूत किया जाएगा वाहन और भीड़ नियंत्रण के लिए -ख आधारित उउढत प्रणाली लागू की जाएगी। त्रेक्षश्रश कंपनी के साथ -ख सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के तहत समझौता किया गया है। पुलिस विभाग में होगी नई भर्ती १०,५०० रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। हर साल ७,०००-८,००० पद रिक्त होते हैं, जिन्हें समय पर भरा जाएगा। पिछले तीन वर्षो में ३५,८०२ पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए महाराष्ट्र को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मौलाना आज़ाद की सौगात, १५०...

को भी पैसा न दें और सीधे जिला प्रबंधक इमरान कादरी या संचालक शेख तैय्यब से संपर्क करें।

इमरान कादरी की अनुशासनपूर्ण ईमानदारी

बीड़ जिले के जिला प्रबंधक इमरान कादरी पिछले कई वर्षो से निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों और व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। महामंडल की योजनाओं के तहत योग्य व्यक्तियों का चयन करते हुए वे हमेशा निष्पक्ष और अनुशासित तरीके से कार्य करते हैं। उनके काम में पारदर्शिता और नियमबद्धता हमेशा बनी रहती है।

१८५७ के संग्राम में बहादुर शाह ...

इतिहासकार पंडित सुंदरलाल लिखते हैं कि यह संस्था लोकतंत्र पर आधारित थी, लेकिन सेना पर इसका नियंत्रण न होने के कारण यह असफल रही।

हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए तीन घोषणाएं

इसी बीच, बहादुर शाह ने तीन सार्वजनिक घोषणाएं कीं, जिनमें हिंदू और मुस्लिम जनता से देश, धर्म और स्वतंत्रता के लिए संग्राम करने की अपील की गई थी। १८५७ के विद्रोह के दौरान हिंदू-मुस्लिम एकता बनाए रखने का उनका प्रयास स्वतंत्रता संग्राम की एक विशेषता है।

जब दिल्ली की जामा मस्जिद में रूढ़िवादी मुस्लिमों ने ईद के दिन गाय की कुर्बानी की घोषणा की, तो चूंकि सैनिकों में बड़ी संख्या हिंदू थे, बहादुर शाह और अन्य नेता चाहते थे कि धार्मिक कारणों से फूट न पड़े। हालांकि, सम्राट के सलाहकार हकीम एहसान उदौला ने मौलवियों के फैसले को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बहादुर शाह ने दृढ़ता से ऐलान किया कि जो भी गाय की कुर्बानी देगा, उसे तोप के मुंह से उड़ाया जाएगा। ईद के दिन उन्होंने स्वयं भेड़ की कुर्बानी दी और एक उदाहरण प्रस्तुत किया।

परिवार के नरसंहार और बहादुर शाह की कैद

जब विद्रोही सैनिक बहादुरी से युद्ध कर रहे थे, तब उनकी पत्नी ज़ीनतमहल ने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ गुप्त रूप से समझौते की कोशिशें शुरू कर दी थीं। लगातार हो रही सैनिकों की हार से बहादुर शाह निराश हो चुके थे और आत्महत्या करने या दिल्ली छोड़ने की धमकी दे रहे थे। वे इस कठिन समय में अपनी कविताओं में सांत्वना खोज रहे थे।

दिल्ली पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद बहादुर शाह और उनके परिवार ने दिल्ली के पास हुमायूं के मकबरे में शरण ली। २१ सितंबर १८५७ को मेजर विल्सन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन, बहादुर शाह के दो बेटे मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान और पोते मिर्ज़ा अबू बकर को बेरहमी से मार दिया गया। मेजर हडसन ने उन्हें बंदी बनाकर दिल्ली लाया।

ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने राजकुमारों के कटे हुए सिर सम्राट और उनकी बेगम के सामने तश्तरी में रख दिए। बहादुर शाह ने यह देख कर कहा, ख़ुदा! तैमूर के वंशज अपने पिता के पास ऐसे ही खूनी उपहार लाते हैं।

बहादुर शाह का अंत

अंग्रेजों ने मुग़ल वंश के अंतिम सम्राट के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्हें एक गंदे कमरे में कैदी की तरह रखा गया। इस दौरान, उन्होंने कोयले से जेल की दीवारों पर अपनी कविताएं लिखीं। आखिरकार, अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा (अब म्यांमार) के रंगून में कैद कर दिया, जहां ७ नवंबर १८६२ को ८७ वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ज़ीनतमहल का निधन १८८२ में वहीं हुआ।

इतिहास में बहादुर शाह जफर का स्थान

यद्यपि बहादुर शाह १८५७ के संग्राम में पूरी तरह असफल रहे, लेकिन हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए किए गए उनके प्रयास उन्हें इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द्र का संदेश दिया।

उनकी लिखी यह अमर पंक्ति उनकी व्यथा को दर्शाती है – कितना बदनसीब है जफ़र' दफ्न के लिए, दो गज़ ज़मीन भी न मिली कू-ए-यार में'।

(पंतप्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा बहादुर शाह जफर की मजार पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।)

अमेरिका में भारतीय...

और खान को सूचित किया कि सरकार ने उनका वीजा रद्द कर दिया है.

सूरी के वकील ने कही ये बात

सूरी के वकील हसन अहमद ने खान की रिहाई के लिए दायर याचिका में तर्क दिया है कि उनकी गिरफ्तारी का कारण उनकी पत्नी का फलस्तीनी मूल का अमेरिकी नागरिक होना है. वकील का कहना है कि सरकार को संदेह है कि सूरी और उनकी पत्नी अमेरिकी विदेश नीति के तहत इजरायल के प्रति अपनाए गए रुख के विरोधी हैं, जिसके चलते उन्हें निशाना बनाया गया है.सूरी पर फिलिस्तीनी संगठन हमास का प्रचार करने का आरोप लगाया गया है, जिसे अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है. इसके अलावा, उन पर एक ज्ञात या संदिग्ध आतंकी के साथ करीबी संबंध रखने का भी आरोप है.

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने बयान में कही ये बात

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की सहायक सचिव ट्रिशिया मैक्लॉघलिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सूरी जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में छात्र थे और वहां हमास का प्रचार कर रहे थे. वह सोशल मीडिया पर यहूदी-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने में सक्रिय थे.

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com